



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

नई विल्ली, शुक्रवार, जून 25, 1982/आषाढ 4, 1904

No. 263]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 1982/ASADHA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(प्रौद्योगिक विकास विभाग)

मार्गेश

नई विल्ली, 25 जून, 1982

का. सं. 441(अ)/18ब० छ०/आई० डी० लार० ए०/82:—  
केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951  
(1951 का 65) की धारा 18ब० की उपधारा (1) के खण्ड (ब)  
का प्रवर्त विवितों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय  
प्रौद्योगिक विकास विभाग (का) प्रावेश सं. 411(अ)/18 व छ  
माई डी भार ए/78, तारीख 27 जून, 1978 (जिसे इसमें इसके  
पश्चात उक्त प्रावेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त  
प्रावेश के एकप्रकार में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्ण प्रवृत्त ऐसी सभी  
संविदाधीनों, सम्पत्ति हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी  
प्रावेशों या अन्य लिखितों (उससे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं  
के प्रतिभूत वायिकों से संबंधित है) का प्रवर्तन जिनका मंसर्स इन्वेक  
दायरे से लिमिटेड, कलकत्ता नामक प्रौद्योगिक उपकरण या ऐसे प्रौद्योगिक  
उपकरण की स्वामित्व कम्पनी एक उपकरण है या जो ऐसे प्रौद्योगिक उपकरण  
या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा  
और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार,  
विवेषाधिकार, वाप्तताएं और वायिक उक्त अवधि के लिए निलम्बित  
रहेंगी;

और उक्त धारेश की अवधि को 26 जून, 1982 तक, जिसमें यह  
दिन भी सम्मिलित है, और तिरंगेरेत किया गया था, देशी सरकार के  
उद्योग मंत्रालय (प्रौद्योगिक विकास विभाग) का प्रावेश सं. 515(अ)-  
18ब०/आई० डी० लार० ए०/81, तारीख 26 जून, 1981;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त प्रावेश की  
अवधि को एक वर्ष की प्रतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जाता  
जाएगा;

परन्तु, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम,  
1951 (1951 का 65) की धारा 18ब० की उपधारा (2) [द्वारा  
प्रवर्त विवितों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रावेश की अवधि को  
26 दिसम्बर, 1982 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, उस साल  
की प्रतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[का. सं. 2(20)/80-सीयूएस]

रा० कु० भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 1982

S.O. 441(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the  
Order of the Government of India in the Ministry  
of Industry (Department of Industrial Development)

No. 411(E)/18FB/IDRA/78, dated the 27th June, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the Industrial undertaking known as Messrs. Incheek Tyres Limited, Calcutta, or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said Order was extended up to and inclusive of the 26th June, 1982, vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 515(E)-18FB/IDRA/81, dated the 26th June, 1981.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of six months up to and inclusive of the 26th December, 1982.

[F. No. 2(20)/80-Cus.]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.